Development Programme given in the statement enclosed. Based on review of works under the Programme Central assistance of Rs. 289.16 lakh for the year 1993-94 and Rs. 162.66 lakh for the year 1994-95 was released to the State Government.

Statement

Irrigation Projects in Madhya Pradesh under the Centrally Sponsored Command Area Development Programme :

S. No.	Name of Projects
1.	Tawa
2.	Chambal
3.	Aodha
4.	Barna
5.	Halali
6.	Kolar
7.	Naren
8.	Kethan
9.	Hasdeo
10.	Kharung
11.	Maniyari
12.	Ghonga
13.	Mahanadi
14.	Pairi
15.	Tandula
16.	Tonk
17.	Bolar
18.	Kodar
19.	Upper Wainganga
20.	Bagh
21.	Harsi
22.	Rampur Makroda
23.	Rani Avanti Bai (Bargi)

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

1903. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा खेतों को पानी पहुंचाने और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने के लिए पिछले बीस वर्षों से देश में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है पिछले दशक के दौरान सिंचाई की अधिष्ठापित क्षमता और उपयोगिता क्षमता के बीच अंतर को कम नहीं किया जा सका ;

(ग) यदि नहीं, तो छठी, सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजनावधियों के अंत में देश में सिंचाई की अधिष्ठापित क्षमता और उपयोगिता क्षमता के बीच कितना अंतर था ;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस अंतर को कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम द्वारा दूर करने के लिए कोई समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) और (ख) सिंचाई की प्रतिष्ठापित क्षमता और उसके वास्तविक उपयोग के मध्य अंतर को कम करने के लिये कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन 1974-75 से किया जा रहा है। पिछले दशक के दौरान सृजित क्षमता और उपयोग की गई क्षमता दोनों में वृद्धि हुई है । इसलिए प्रतिष्ठापित क्षमता और इसके उपयोग के मध्य अंतर कम नहीं हुआ है।

(ग) छठी, सातवीं योजना के अंत तक और 8वीं योजना के प्रारंभ में सिंचाई की प्रतिष्ठापित क्षमता और इसके उपयोग के अंतर क्रमशः 2.37 मिलियन हेक्टेयर 3,51 मिलियन हेक्टयर और 3.42 मिलियन हेक्टेयर रहे ।

(घ) से (च) सृजित क्षमता और इस उपयोग के मध्य अन्तर रहेगा चूंकि नई क्षमता निरन्तर सृजित की रही है । तथापि, केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आन फार्म विकास कार्य पूरे करने के लिए निम्नलिखित समय-सीमाओं के बारे में राज्य सरकारों को जनवरी, 1991 में सूचित किया गया था :

(क) नई परियोजनाएं

(i) 10,000 हेक्टेयर के कृष्य कमान क्षेत्र वाली परियोजनाएं	5 वर्ष
(ii) 10,000 से 50,000 हेक्टेयर तक	8 वर्ष
(iii) 50,000 से 1,00,000 हेक्टेयर तक	10 वर्ष
(iv) 1,00,000 हेक्टेयर से अधिक	15 वर्ष

(ख) चल रही परियोजनाएं

फील्ड चैनलों के अन्तर्गत शामिल करने के लिए शेष कृष्य कमान क्षेत्र

(क) 1,00,000 हेक्टेयर तक	5 वर्ष
(ख) 1,00,000 से 2,00,000 हेक्टेयर तक	8 वर्ष
(ग) 2,00,000 हेक्टेयर से अधिक	10 वर्ष

भूमिगत जल की उपलब्धता

1904. श्री राम जेठमलानी :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जल के लगातार दुरुपयोग के कारण, भूमिगत जल की उपलब्धता में कमी हो रही है ;

(ख) यदि हां तो वर्ष 1950-51 और 1990-91 के दौरान देश में भूमिगत जल की उपलब्धता के संबंध में प्रति व्यक्ति औसत क्या था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने देश में भूमिगत जल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना बनाई है ;

(घ) यदि हां, तो योजना की विस्तृत रूपरेखा क्या है और इस योजना के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता होने का अनुमान है तथा इस योजना के अंतर्गत कितनी अतिरिक्त भूमि की सिंचाई करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ङ) क्या सरकार ने इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए अंतिम निर्णय ले लिया है ; और

(च) यदि हां, तो इस योजना का कार्यान्वयन कब शुरू किया जाएगा और इसे कब तक पूरा किया जाएगा ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) : (क) देश के कुछ क्षेत्रों में भूतल उपलब्धता की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और कुछ में घट रही है ।

(ख) जहां तक प्रति व्यक्ति औसत भूमिगत जल उपलब्धता का संबंध है, वर्ष 1950-51 के दौरान कोई विशिष्ट आकलन नहीं किए गए । तथापि, 1990-91 के दौरान प्रतिव्यक्ति भूमिगत जल की उपलब्धता 535 घनमीटर का पता लगाया गया है ।